

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2006

विषय: मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल के सभी न्यायालय कक्षों में स्थापित कम्प्यूटरों को आपस में नेटवर्किंग (L.A.N.) से जोड़े जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-428/UHC/Admn.B/Comp./2005, दिनांक 17.2.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल के सभी न्यायालय कक्षों में स्थापित कम्प्यूटरों को आपस में नेटवर्किंग (L.A.N.) से जोड़े जाने हेतु एन०आई०सी०एस०आई० से प्राप्त आगणन रु० 10,86,736/- प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 10,86,736/- (रुपये दस लाख छियासी हजार सात सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश वर्ष 2006 के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही कार्य सम्पादित कराया जाय ।
- (2) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (3) सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सामग्री का परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।
- (5) कार्य को समय से पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।
- (6) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-432/XXXV(1)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव ।

संख्या-12-एक(2)/XXXVI(1)/2006-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
5. निदेशक, एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।